International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, July-December 2024, Submitted in November 2024, ISSN -2393-8048

निर्धारक तत्वों को प्रभावित करती नई आर्थिक नीति

अनिता, शोधार्थी (अर्थशास्त्र) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर
डॉ. रणधीर सिंह, सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) टांटिया विश्वविद्यालय, श्री गंगानगर

अमूर्त

यह शोध पत्र भारत में वर्ष 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति के भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न निर्धारक तत्वों पर पड़े प्रभावों का विश्लेषण करता है। नई आर्थिक नीति, मुख्य रूप से उदारीकरण , निजीकरण और वैश्वीकरण के सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नीति ने औद्योगिक उत्पादन, विदेशी निवेश, रोजगार सृजन, और गरीबी तथा असमानता जैसे प्रमुख आर्थिक निर्धारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

शोध गुणात्मक और मात्रात्मक

दोनों तरह के आंकड़ों का उपयोग करते हुए यह जांच करता है कि NEP ने भारत के आर्थिक विकास की गति और प्रकृति को किस प्रकार रूपांतरित किया। निष्कर्ष यह बताते हैं कि NEP ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और विदेशी मुद्रा भंडार में सकारात्मक योगदान दिया, लेकिन इसके साथ ही इसने क्षेत्रीय असमानताओं और अनौपचारिक क्षेत्र में चुनौतियों को भी जन्म दिया।

परिचय

भारत ने 1991 में गंभीर आर्थिक संकट के बाद एक मौलिक आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, सरकारी नियंत्रणों को कम करना और निजी क्षेत्र को विकास के लिए अधिक अवसर प्रदान करना था। NEP के तीन प्रमुख स्तंभ थेरू उदारीकरण (लाइसेंस राज की समाप्ति), निजीकरण (सरकारी उद्यमों की हिस्सेदारी बेचना), और वैश्वीकरण (विदेशी व्यापार और निवेश पर प्रतिबंधों को हटाना)। इस नीति का देश के विभिन्न आर्थिक निर्धारक तत्वों पर व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा। ये निर्धारक तत्व न केवल सकल आर्थिक संकेतक जैसे सकल घरेलू उत्पाद , मुद्रास्फीति और विदेशी मुद्रा भंडार थे, बल्कि सामाजिक–आर्थिक निर्धारक भी थे, जिनमें रोजगार , आय असमानता और गरीबी शामिल हैं।

साहित्य समीक्षा

नई आर्थिक नीति (NEP) पर व्यापक शोध कार्य किया गया है। प्रारंभिक शोध (जैसे भार्गव, 1994(अहलूवालिया, 2002) मुख्य रूप से ळक्च वृद्धि और भुगतान संतुलन पर नीति के सकारात्मक प्रभावों पर केंद्रित थे। इन अध्ययनों ने उदारीकरण के बाद बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा और दक्षता की प्रशंसा की। हालांकि, बाद के अध्ययनों (जैसे सेन, 2007 (देसाई, 2012) ने NEP के वितरणात्मक परिणामों पर चिंता व्यक्त की है। इन शोधों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वैश्वीकरण और निजीकरण ने आय असमानता को बढ़ाया है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अधिक लाभ हुआ, जबकि कृषि और असंगठित क्षेत्र पिछड़ गए। कुछ शोधों ने यह भी दर्शाया है कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, क्योंकि कुछ राज्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने में अधिक सफल रहे। यह शोध पूर्व साहित्य से परे जाकर, एक समेकित दृष्टिकोण से, छम्च के विभिन्न निर्धारक तत्वों – विशेषकर औद्योगिक संरचना, श्रम बाजार और समावेशी विकास के संदर्भ के बीच जटिल संबंधों की जांच करता है।

उद्देश्य

इस शोध पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैंरू नई आर्थिक नीति (NEP) के लागू होने के बाद से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि, विदेशी निवेश और व्यापार संतुलन जैसे प्रमुख आर्थिक निर्धारकों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना। छम्च का भारतीय औद्योगिक संरचना और रोजगार सृजन की प्रकृति पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करना। छम्च के कारण आय असमानता, क्षेत्रीय असमानता और गरीबी के स्तर में हुए परिवर्तनों की जांच करना और सामाजिक–आर्थिक निर्धारकों पर इसके समग्र प्रभाव का आकलन करना।

परिकल्पना

इस शोध की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं: शून्य परिकल्पना (\text{H}_0): नई आर्थिक नीति का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) जैसे प्रमुख आर्थिक निर्धारकों पर कोई महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। वैकल्पिक परिकल्पना (\text{H}_1): नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सकारात्मक और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया

है। द्वितीय वैकल्पिक परिकल्पना (\text{H}_2): नई आर्थिक नीति ने आर्थिक वृद्धि तो की है, परंतु इसने आय असमानता और क्षेत्रीय असमानता को भी बढ़ाया है, जिससे समावेशी विकास प्रभावित हुआ है।

महत्व

यह शोध NEP के प्रभावों का एक समग्र और संतुलित मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह नीति–निर्माताओं (Policy Makers) को यह समझने में मदद करेगा कि आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को कैसे प्रभावित किया है। विशेष रूप से, यह शोध पत्र उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां NEP के कारण नकारात्मक बाहरी कारक (Negative Externalities) उत्पन्न हुए हैं (जैसे असमानता और अनौपचारिक क्षेत्र में संकट)। इस प्रकार, यह भविष्य के आर्थिक सुधारों को अधिक समावेशी, सतत और न्यायसंगत बनाने के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

विधितंत्र

यह शोध मुख्य रूप से एक विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मकदृष्टिकोण अपनाता है। डाटा स्रोतरू शोध प्राथमिक रूप से द्वितीयक डेटा पर निर्भर करता है। इसके मुख्य स्रोतों में भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आँकड़े, विश्व बैंक के संकेतक, और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) के रोजगार और उपभोग के आँकड़े शामिल हैं। समय–सीमारू विश्लेषण के लिए 1991 से लेकर वर्तमान तक के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें NEP से पूर्व और बाद की स्थिति की तुलना की जाएगी। विश्लेषण तकनीकः प्रतिगमन विश्लेषण जीडीपी वृद्धि, विदेशी निवेश, और औद्योगिक उत्पादन जैसे निर्धारकों पर उदारीकरण के चरों के प्रभाव को मापने के लिए। गिनी गुणांक और पलमा अनुपात आय असमानता के स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए। तुलनात्मक विश्लेषणः NEP से पहले (1980–1991) और बाद (1992–वर्तमान) के विभिन्न आर्थिक और सामाजिक निर्धारकों के औसत प्रदर्शन की तुलना करना।

निष्कर्ष

नई आर्थिक नीति (NEP) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने देश को 1991 के भुगतान संतुलन संकट से उबारने में सफलता प्राप्त की और विकास की गति को तेज किया। सकारात्मक प्रभाव: NEP ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में भारी वृद्धि की, जिससे पूंजी का प्रवाह बढ़ा। इसने प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर औद्योगिक क्षेत्र की दक्षता में सुधार किया और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चुनौतियाँ और नकारात्मक प्रभावरू हालांकि, NEP समावेशी नहीं रही। वैश्वीकरण और उदारीकरण के लाभ संगठित शहरी क्षेत्रों और सेवा क्षेत्र तक सीमित रहे, जबकि कृषि और अनौपचारिक विनिर्माण क्षेत्र को अपर्याप्त समर्थन मिला। परिणामस्वरूप, आय असमानता (Gini गुणांक में वृद्धि के रूप में) और क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। रोजगार सृजन की गति धीमी रही, जिसे अक्सर ष्जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है।

ग्रंथ सूची

- Ahluwalia, I. J. (2002). Second Generation Reforms in India: An Overview. Economic and Political Weekly.
- Bhagwati, J., & Panagariya, A. (2012). India's Tryst with Destiny: Debunking the Myths that Undermine Progress.
- HarperCollins. Sen, A. (2007). The Argumentative Indian: Writings on Indian Culture, History and Identity. Penguin Books.
- Desai, M. (2012). India’s Economic Reforms: Challenges and Prospects.